

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025 (Bill Passed)

THE MINISTER OF COAL; AND MINISTER OF MINES (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir,
I beg to move^{*} :

?That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration.?? (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, एक मिनट आप रूकिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आपने आज सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला विचाराधीन है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है, वह सही है ।

माननीय मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : महोदय, वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के माइनिंग सेक्टर की स्थिति क्या थी, यह सभी लोगों को मालूम है ।? (व्यवधान) सारा देश इसे जान चुका है ।? (व्यवधान) कांग्रेस के राज में माइंस के बारे में हर दिन मीडिया में, हर दिन हेडलाइंस ब्रेकिंग न्यूज में होती थी ।? (व्यवधान) अलग-अलग कोर्ट्स के द्वारा अलग-अलग जजमेंट भी दिए गए ।? (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशंस का सिलसिला भी चला था ।? (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में, वर्ष 2021 में, वर्ष 2023 में एमएमडीआर एक्ट में तीन बार रिवॉर्स लाए गए ।? (व्यवधान) आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस एक्ट में 6 बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स संसद के सामने लाए गए हैं, जो माइनिंग सेक्टर के हित के लिए हैं ।? (व्यवधान) आज देश की डिमांड है कि माइनिंग सेक्टर के द्वारा रोजगार बढ़ना चाहिए, माइनिंग सेक्टर के द्वारा देश को क्रिटिकल मिनरल्स मिलने चाहिए ।? (व्यवधान) भारत के माइनिंग सेक्टर को देखते हुए आज ये बदलाव इस एक्ट में लाये गए हैं ।? (व्यवधान)

महोदय, वर्ष 2014 से पहले जो पार्टी सत्ता में थी, उस समय माइंस का अलॉटमेंट कैसे होता था?? (व्यवधान) एक सफेद पेपर के ऊपर कुछ लोग लिखकर देते थे और उन्हें ही माइंस अलॉटमेंट होता था ।? (व्यवधान) आज स्थिति क्या है? ? (व्यवधान) वर्ष 2014 से लेकर आज तक एक भी ऐसा इंसिडेंट नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में नहीं आया है ।? (व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के साथ आज माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए हैं ।? (व्यवधान) पहले क्या स्थिति थी? ? (व्यवधान) पहले पूरा भ्रष्टाचार होता था ।? (व्यवधान) पूरे माफिया लोग इसमें होते थे ।? (व्यवधान) आज उस स्थिति में पूरा बदलाव हो गया है ।? (व्यवधान) आपको मालूम है कि उनके राज में जो अलॉटमेंट हुए थे, लगभग 104 कोल माइंस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके उनका ऑक्शन करने के लिए आदेश दिया था ।? (व्यवधान) उस समय यह स्थिति थी ।? (व्यवधान) मैं बताना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी के आदेश पर जो बदलाव आज आए हैं, उनका पूरा समर्थन आज देश की जनता कर रही है ।? (व्यवधान)

इसीलिए मैं आज इन छह अमेंडमेंट्स के लिए सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ । भारत के मिनरल्स की आज पूरी दुनिया में पुकार है ।? (व्यवधान) जिओ पॉलिटिक्स हो रही है, क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड हैं । आज सेल फोन से लेकर विमान तक, एग्रीकल्चर से लेकर हरेक सेक्टर तक क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है ।? (व्यवधान) डिफेंस से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है । इसीलिए आज जो छह अमेंडमेंट्स आए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों से सुझाव लेकर सर्वसम्मति से इन अमेंडमेंट्स को पास कराएं । मैं इसके लिए अनुरोध कर रहा हूँ ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

?That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration.?

? (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी अपील कर रहे हैं कि सभी लोगों के सुझाव लिए जाएं, क्योंकि उन्होंने आज विस्तार से वर्तमान सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला है और इससे पूर्ववृत्ती सरकार की नीतियों पर भी प्रकाश डाला है । जिस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स के विकास के लिए कुछ संशोधन लेकर आए हैं, उन क्रिटिकल मिनरल्स से स्टेट्स को ही फायदा होगा । यह बिल स्टेट गवर्नमेंट्स के हित में है ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्रिटिकल मिनरल्स से जो रॉयल्टी आएगी, वह आपके स्टेट्स को जाएगी । यह बिल भारत सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, लेकिन इसका जो पैसा आएगा, क्रिटिकल मिनरल्स की जो परमिशन दी जाएगी, उसकी जो भी रॉयल्टी होगी, वह सभी राज्यों को जाएगी । राज्यों में पैसा जाए, क्या आप इसका विरोध करेंगे?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर राज्यों में किसी अमेंडमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस बिल से लाभ होना है, तो क्या आप इसका विरोध करना चाहेंगे? क्या आप राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं? इसमें आपके सुझाव जानने हैं । इसमें आपकी क्या राय है?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह जो अमेंडमेंट बिल आया है, यह क्रिटिकल मिनरल्स के स्कोप को बढ़ाने के लिए है । चाहे वह कोबाल्ट हो, चाहे आयरन ओर हो, चाहे कोल हो, उसमें जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस चर्चा में भाग लीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती मालविका देवी जी ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Hon. Chairman, Sir, I rise today with a heart full of hope and a vision for a stronger, more prosperous Bharat. I rise to speak in support of a landmark piece of legislation, the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025.? (*Interruptions*) This is a *Sankalp Patra*, a solemn promise and pledge to the people of our nation. It is a promise to unlock the immense treasures that lie buried in the heart of our motherland, and to ensure that this wealth becomes a tool for the empowerment of every single *Bharatiya*.? (*Interruptions*)

Beneath our feet is a repository of our past glory and the seed of our future prosperity.? (*Interruptions*) But for decades, the path to this prosperity has been riddled with obstacles. Our mining sector has been held hostage to outdated laws and regulatory constraints which have restricted ease of doing business.? (*Interruptions*) The past Governments had been unfair and we need to look into the annals of history as they did not do justice to our resources.? (*Interruptions*)

On the 21st December, 1957, the Minister of Mines and Oil, Shri K. D. Malaviya, introduced the Mines and Minerals (Regulation and Development) Bill, 1957.? (*Interruptions*) He treated the private sector with suspicion. Major minerals such as coal, lignite, minerals, oils, and iron ore under this Bill were not allowed for public sector.? (*Interruptions*) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, was further amended in 1972, and it was amended again in 1986. But the severe regulatory regime introduced by the MNDR in 1957 and the statutory amendments of 1972 and 1986 continued till the early 90s.? (*Interruptions*) The amendments in the Bill seemed to perpetuate the control of the Government. Today, Modi ji's dream is different. He wants to give out control of that. He is not the one who wants to control everything.? (*Interruptions*) He is working towards

strengthening Bharat, the story of Bharat and unchaining the potential of India's mines and resources.? (*Interruptions*)

The Bill is a beacon of transparency, a catalyst for growth and a testament to our commitment to Antyodaya.? (*Interruptions*) The Bill will empower Bharat in three fundamental ways. First, it addresses the urgent need for critical minerals and secures their supply chains. From lithium to cobalt and other rare earth elements, these minerals drive India's economic growth story.? (*Interruptions*)

They are indispensable to a clean future through their usage in EVs and renewable energy.(*Interruptions*) It would not be far from the truth to say that these minerals will drive Bharat's Amrit Kaal.(*Interruptions*) The Bill empowers the Central Government to exclusively auction these mineral blocks, ensuring standardisation and reducing delays, which was a big problem in the past.(*Interruptions*) By fast-tracking the auction process, it will reduce our import dependence and enhance our strategic autonomy.(*Interruptions*)

Secondly, the technological and engineering prowess of Indian talent will not be limited to our national boundaries.(*Interruptions*) The amendment widens the scope of the National Mineral Exploration Trust (NMET) by allowing to fund exploration activities abroad as well.(*Interruptions*) In the face of challenges to the global supply chains, this forward-looking decision by our Modi Sarkar will secure access to resources.(*Interruptions*) The Bill has managed to exemplify the *mantra* of 'सबका साथ, सबका विकास'।?? (व्यवधान)

Earlier, our private sector used to hesitate about mineral exploration due to the high risk nature of the enterprise.(*Interruptions*) However, by introducing this, the Government has come forward with a clear message to the corporations. We stand shoulder to shoulder with you.(*Interruptions*) We want to take India forward.(*Interruptions*) We want to make Bharat successful.(*Interruptions*) The licence provides an incentive, a share in the auction value of a mining lease, if a private explorer proves a resource.(*Interruptions*)

The Bill enshrines the principle of sustainable and inclusive development.(*Interruptions*) We are not just focused on what we extract from the earth, but also on what we must give back to the people and the environment.(*Interruptions*) The strengthened provisions of the District Mineral Foundations (DMFs) are a revolutionary step.(*Interruptions*) This is not charity; it is the right of everyone.(*Interruptions*)

Odisha is a land of Gods. It is the land of Mahaprabhu Jagannath.(Interruptions) It is also blessed with abundance of nature's bounty, which sadly was never used.(Interruptions) For the people of Kalahandi, Keonjhar, Sundargarh, Koraput and Mayurbhanj, who still live amidst some of the richest iron ore and bauxite deposits, this Bill brings a promise of better life.(Interruptions) The revenue generated from the transparent auction of these mines will transform the face of these districts.(Interruptions)

माननीय सभापति : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI MALVIKA DEVI: I am just concluding.(Interruptions)

The DMF fund will bring a torrent of development.(Interruptions) Think of the tribal communities of Kalahandi and how they will develop.(Interruptions) The Bill is an emotional contract with the people of Odisha.(Interruptions)

माननीय सभापति : कृपया अब आप अपने भाषण को समाप्त करें । आपकी बातें आ गयी हैं ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI MALVIKA DEVI: Sir, I conclude with this last line. ?भारत की खान, मोदी जी का मान ।?? (व्यवधान)

Thank you.(Interruptions)

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): Thank you hon. Chairperson Sir. I rise to speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025.(Interruptions)

In the last 10 years under the NDA Government, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, India's mining sector has seen strong and sustained growth.(Interruptions) Since 2015, 385 mineral blocks have been auctioned with 50 mines already in production. Iron ore production more than doubled from 129 million tonnes in 2014-15 to a record 289 million tonnes in 2024-25.(Interruptions) Limestone production rose significantly from 295 million tonnes to 406 million tonnes in the same period.(Interruptions) The sector's Gross Value Addition increased from Rs.2.9 lakh crore to Rs.33.18 lakh crore between 2014-15 and 2022-23.(Interruptions) This Bill builds on that progress by improving transparency,

accelerating approvals, and empowering States. These are all essential steps towards India's mineral security and continued economic growth.(Interruptions)

I wish to highlight some of the most commendable provisions of the Bill.(Interruptions) Clause 2, which defines and facilitates a regulated mineral exchange, is a game-changer.(Interruptions) This will bring transparency and fair price discovery aligning us with global benchmarks like the London Metal Exchange.(Interruptions) It eliminates the opaque practices of the past, boosts investor confidence, and ensures that the public gets its due share of the mineral wealth.(Interruptions)

Clause 3 allows for a one-time contiguous area extension for deep-seated mineral leases.(Interruptions) This is a pragmatic approach that will significantly accelerate the exploration and production of critical minerals like lithium, cobalt, and rare earths, which are vital for our energy transition and strategic resilience.(Interruptions)

Clause 6, which removes the need for prior Central Government approval for certain licences, is a powerful example of cooperative federalism.(Interruptions) By empowering States, this provision streamlines the licensing process, reduces red-tapism and enables faster operationalisation of mines.(Interruptions) This is a win for both State revenues and the national goal of mineral self-sufficiency.(Interruptions)

Coming to my home State, Andhra Pradesh, while the Central Government has been driving progressive reforms, unfortunately, our State's mining sector has faced severe setbacks in the last five years. ? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

? (Interruptions)

SHRI G. LAKSHMINARAYANA: The previous administration's so-called 'free-sand' policy was disastrous. It resulted in widespread environmental destruction, including riverbed degradation, and led to an estimated loss of near about Rs. 7,000 crore. But today, under the dynamic leadership of our new Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, things are finally turning around. We are bringing transparency back. Our new Mines and Minerals Policy, 2025, will resolve nearly 1,900 pending cases through a one-time settlement scheme. By reviving the first-

come, first-served policy for mines and minerals, we are encouraging new ?
(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Your point is already well taken. Kindly conclude.

? (Interruptions)

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी बात समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

SHRI G. LAKSHMINARAYANA: In Andhra Pradesh and other States, royalty on limestone is levied based on mined quantities, but proximity of limestone mines to cement plants makes accurate estimation difficult, leading to revenue losses. ?
(Interruptions) To address this, royalty can be charged on a pro rata basis on cement production, calculated from the limestone required to manufacture it. ?
(Interruptions) This method will simplify monitoring and improve transparency, and ensure that the State gets its rightful revenue without relying solely on direct mine output measurements. Clinker and fly ash are sometimes mixed to make bricks. ?
(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You have already spoken and your point has been well taken.

Gurumoorthy ji.

? (Interruptions)

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Thank you, hon. Chairman Sir for giving me the opportunity to address the Mines and Minerals Amendment Bill, 2025, which seeks to modernise India's mining laws. The Bill introduces several transformative reforms but also raises serious concerns that must be addressed to ensure inclusive and responsible development. ? (Interruptions)

I will address some few positive points. ? (Interruptions) In Section 6A, the Bill allows a one-time expansion of mining lease areas for deep-seated minerals ? up to 10 per cent for leaseholders and 30 per cent for composite licence holders. This enables mining of contiguous deposits deeper than 200 metres, reducing operational costs and improving resource utilisation. ? (Interruptions)

Under Section 15B and the Eighth Schedule, strategic and critical minerals added to existing leases will not incur additional charges. ? (Interruptions) This benefits

industries essential to defence, clean energy, and electronics, while reducing India's import dependence in key sectors.

Under Sections 8A and 18B, the 50 per cent sales cap on captive mines is removed, allowing full sale of surplus production. Additionally, the establishment of regulated mineral exchanges will ensure transparent, efficient, and competitive mineral trading. ? (Interruptions)

There is some concern. This Bill omits explicit requirements for compliance with Article 338A(9), the Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, and the Forest Rights Act. This undermines tribal rights in Scheduled Areas.

HON. CHAIRPERSON: Shri Brijmohan Agrawal ji.

? (Interruptions)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय श्री जी. किशन रेड्डी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। उनके द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है।? (व्यवधान) यह एक ऐसा बिल है, जिसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के खनन एवं वन क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए 3 प्रतिशत डीएमएफ फंड को बढ़ाया है और रॉयल्टी को तीन प्रतिशत किया है। इससे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूँ। छत्तीसगढ़ में 37 परसेंट कोल और लिग्नाइट है, 22 परसेंट आयरन है, 36 परसेंट लाइमस्टोन है, 12 परसेंट बॉक्साइट है।? (व्यवधान) परंतु इसके बावजूद भी उस क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं, उनके विकास के बारे में अगर किसी ने सोचा तो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा, जी किशन रेड्डी जी ने सोचा। इनके माध्यम से वहां तेजी से विकास होगा।? (व्यवधान)

हमारे ऐसे जो मिनरल्स हैं, जैसे लिग्नाइट है, लिथियम है, कोबाल्ट है, दुर्लभ मृदा है, छत्तीसगढ़ में लिथियम मिला है। ? (व्यवधान) उन खनिजों के माध्यम से हमारी बैट्रीज़ के लिए जो लिथियम मिलता है। ? (व्यवधान) उस लिथियम के माध्यम से पूरे देश की विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारी सोलर ऊर्जा भी तेज़ी से विकसित होगी। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अब आप अपनी बात को समाप्त कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि डीएमएफ फंड का जो उपयोग है, वह उन क्षेत्रों में ठीक तरह से हो पाए, इसके लिए रेग्युलेशन इस नियम में लाया गया है। ? (व्यवधान) पूर्व में, कांग्रेस की सरकार के जमाने में कोयला क्षेत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण गरीब क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। ? (व्यवधान) मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ के विकास के

लिए, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए, वंचितों के विकास के लिए यह कानून महत्वपूर्ण है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात आ गई है।

श्रीमती संगीता देव जी।

? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। ? (व्यवधान) आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ? (व्यवधान)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. ? (*Interruptions*)

I rise today in support of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025, and to place on record my strong support for its provisions. ? (*Interruptions*)

This is not just a change in the law; it is a decisive step by our hon. Prime Minister towards securing Bharat's mineral future with foresight, efficiency, and strategic clarity. Minerals today are not only an economic resource; they are a strategic asset. Critical minerals are the new oil. ? (*Interruptions*)

They will power electric mobility, renewable energy, advanced manufacturing, and defence capabilities. Securing them is as important as securing our borders. This Bill addresses several long-standing gaps in our mining framework. ? (*Interruptions*)

श्री जी. किशन रेड्डी : माननीय सभापति जी, भारत की ग्रोथ स्टोरी में माइनिंग सेक्टर एक इम्पोर्टेंट पिलर है। ? (व्यवधान) सारे भारत की ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में रिन्युएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीस में आज क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। ? (व्यवधान) सभापति जी, आज भारत लिथियम में, अलग-अलग सैक्टर्स में विदेश पर डिपेंड है। ? (व्यवधान) भारत में क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन बहुत कम है। ? (व्यवधान) मिनरल बोलें तो कोल और एल्युमिनियम ही था। ? (व्यवधान) आज समय-समय पर, वर्ष 2015 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किया गया है, उस कारण आज हरेक सैक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। ? (व्यवधान) आज मैं जो बताना चाहता हूँ, आज क्रिटिकल मिनरल्स की जो इम्पोर्टेंस है, उसको सभी लोगों को समझना चाहिए। ? (व्यवधान) सोलर पैनल से ले कर विंड टर्बाइन तक, एग्रीकल्चर से ले कर मेडिकल इक्विपमेंट्स तक, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सेल फोन से ले कर विमान तक, डिफेंस से ले कर स्पेस टेक्नोलॉजी तक, हर सैक्टर में आज क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत बड़ी डिमांड है। ? (व्यवधान) इसके लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी। ? (व्यवधान) आदरणीय प्रधान मंत्री जी जिस देश में जाते हैं, उस देश में अगर क्रिटिकल मिनरल्स हैं तो उस टेक्नोलॉजी के लिए, क्रिटिकल मिनरल के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री बहुत प्रयास करते हैं। ? (व्यवधान) लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ? (व्यवधान) भारत सरकार ने भी प्रधान मंत्री जी के

आदेश पर विदेश में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक संस्था भी ऑर्गनाइज़ की है । ? (व्यवधान) आज ?काबिल? नाम से एक पीएसयू भारत सरकार ने क्रिएट की है ।? (व्यवधान) उसके द्वारा आज लिथियम के लिए, अलग-अलग क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हम जांबिया जा रहे हैं, अर्जेंटीना जा रहे हैं । अलग-अलग देशों में जा कर भारत सरकार का, गवर्मेंट टू गवर्मेंट प्लान कर के, एमओयू कर के, उन क्रिटिकल मिनरल्स को भारत में लाने का प्रयास हम कर रहे हैं । ? (व्यवधान) इतना ही नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद, जिस जगह माइनिंग होती है, उस माइनिंग इफेक्टिव एरिया में, माइनिंग इफेक्टिव लोगों के लिए एक डीएमएफ की स्थापना की है । ? (व्यवधान)

डीएमएफ के द्वारा आज माइनिंग इफेक्टिव एरिया, हेल्थ सेक्टर, एंप्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर, रोजगार आदि के विषयों पर काम चल रहा है । ? (व्यवधान) आज मैं बताना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डीएमएफ की स्थापना होने के बाद 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपये का अलग-अलग जिलों में एक्सपेंडीचर किया जा रहा है । ? (व्यवधान) जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, आदरणीय एमपीज़, एमएलएज़ एवं अन्य प्रतिनिधियों के साथ डीएमएफ का काम चल रहा है । ? (व्यवधान)

पहले पूरे माइनिंग सेक्टर को राजनीतिक लोग, उनके परिवार के लोग, उनकी रूलिंग पार्टी के लोग लूटते थे । ? (व्यवधान) आज नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद उनके द्वारा डीएमएफ की स्थापना करके पूरे विलेजेस में इफेक्टिव पीपुल्स के लिए वे काम कर रहे हैं । ? (व्यवधान)

सभापति जी, इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि आज एक यूनिफॉर्म माइनिंग लिस्ट सिस्टम लाया गया है । ? (व्यवधान) आज माइनिंग इफेक्टिव एरियाज़ में डीएमएफ के साथ-साथ NMET के द्वारा एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है । ? (व्यवधान) आज NMET के द्वारा फाइनैसिंग करके बड़ी और छोटी कंपनियां भी आई हैं । ? (व्यवधान) मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पूरा विपक्ष भी इस पर बिल का समर्थन करेगा, क्योंकि गांवों में एंप्लॉयमेंट देने के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी जिंदगी में उजाला लाने के लिए माइनिंग सेक्टर में आज काम हो रहा है । ? (व्यवधान)

सभापति जी, आज कुछ लोगों को माइनिंग सेक्टर में विश्वास नहीं है । ? (व्यवधान) कुछ लोगों को भारत की सेना पर विश्वास नहीं है । कुछ लोगों को सिक्योरिटी फोर्स पर विश्वास नहीं है । ? (व्यवधान) कुछ लोगों को इंडियन इकोनॉमी पर विश्वास नहीं है । ? (व्यवधान) उनको भारत के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है । ? (व्यवधान) उनको भारत की पार्लियामेंट पर विश्वास नहीं है । ? (व्यवधान) उनको भारत की इलेक्शन व्यवस्था पर विश्वास नहीं है और उनको भारत की मीडिया पर भी विश्वास नहीं है । यह बिल माइनिंग सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण पिलर साबित होगा । ? (व्यवधान)

सभापति जी, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और उसमें माइनिंग सेक्टर भी रोजगार का बहुत बड़ा सेक्टर होगा । यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पिलर होगा । इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब इस बिल का यूनेनिमसली समर्थन करें । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मुझे बहुत दुख है कि आप जिस पर डिमांड करना चाहते हैं और जिस पर आप चर्चा की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आप सभी वेल में हैं । आज वह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो ऑब्जर्वेशन दी है, उसके बारे में आपको पता है ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The entire nation is watching what you are doing. I am requesting you. The Supreme Court has made an observation on this particular subject. You must take a note.

? (Interruptions)

माननीय सभापति : आप इस तरह से सदन का काम बाधित नहीं कर सकते हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 12 विधेयक के अंग बनें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

?खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।?

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I rise to move:

?That the Bill be passed?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

17.00 hrs